

[2023] 10 एस सी आर 842:2023 आईएनएससी 647

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

पश्चिम बंगाल और ओआरएस का राज्य।

बनाम

एस. यू. वी. ए. एन. डी. आधिकाड़ी आ ओ. आर. एस.

(2023 की विशेष अनुमति याचिकाएं (आपराधिक) संख्या 6283-6286)

बी.

24 जुलाई, 2023

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश , जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.]

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 -धारा 6 (5)-यू/एस क्षेत्राधिकार का प्रयोग।
6(5) – विभिन्न घटनाओं के संबंध में 30.03.2023 से 03.04.2023 के बीच छह प्राथमिकियां दर्ज की गईं-एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोप विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों को शामिल करते हैं, और कहा कि केंद्र सरकार को 2008 के अधिनियम की धारा 6 (5) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के निर्देश के साथ पूरी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को हस्तांतरित की जानी चाहिए-केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की धारा 6 (5)-इसके अनुसरण में, 10.05.2023 पर दर्ज छह प्राथमिकियां और विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:एन. आई. ए. ने धारा 6 (5) के तहत अपनी शक्तियों के संदर्भ में विशेष रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है-एन. आई. ए. द्वारा की जाने वाली जांच की सटीक रूपरेखा का वर्तमान स्तर पर अनुमान या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है-एन. आई. ए. अदालत द्वारा भी संज्ञान लिया गया-उच्च न्यायालय के फैसले ने पुष्टि की-एस. एल. पी. का निपटारा किया गया।

सी.

डी.

ई.

एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक)
संख्या 6283-6286।

एफ.

2023 के डब्ल्यू. पी. ए. (पी) Nos.151,154,156 और 162 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.04.2023 के निर्णय और आदेश से।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकरनारायण, वरिष्ठ अधिवक्तागण , संजय बसु, अमित भंडारी, निपुण सक्सेना, श्रीसत्य मोहंती, सुश्री अदिति गुप्ता, सुश्री अंजू थॉमस, संजीव कौशिक, सुश्री मंटिका हरियानी, श्रेयस अवस्थी, हिमांशु चक्रवर्ती, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी, भानु मिश्रा, सुश्री मुस्कान सुराना, सारांश भारद्वाज, अर्चित अदलखा, सुश्री सौम्या सक्सेना, आदित्य राज पांडे, सुश्री आस्था शर्मा, अधिवक्तागण याचिकाकर्ताओं के लिए।

जी.

एच.

842 ए.

843

पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. v. एस. यू. वी. ए. एन. डी. आधिकाड़ी आ ओ. आर. एस.

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रणब प्रकाश, अभिषेक सरकार, सुश्री बांसुरी स्वराज, सिद्धेश कोतवाल, सुश्री एना उपाध्याय, सुश्री मान्या हसीजा, निहार धर्माधिकारी, तेजस्वी गुप्ता, सुश्री महामाया चटर्जी, लोकनाथ चटर्जी, राहुल शर्मा, निर्णमेश दुबे, कानू अग्रवाल, अनमोल चंदन, अशोक पाणिग्रही, सुश्री संसृति पाठक, अरविंद कुमार शर्मा, सिद्धेश शिरीष कोतवाल, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश

1. पश्चिम बंगाल राज्य में पुलिस द्वारा छह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गईं। इन प्रथम सूचना रिपोर्टों का विवरण पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दिए गए एक बयान में सारणीबद्ध किया गया है:

सी.

--	--	--	--	--

डी.

ई.

एफ.

जी.

2. एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 27 अप्रैल 2023 के अपने आदेश में कहा कि आरोप विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों को शामिल करते हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें पूरी जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अपने आदेश का उपयोग करें।

एच.

844

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की धारा 6 (5) के अधीन शक्ति। 3.इस प्रकार उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कार्यवाही का निपटारा किया कि सभी प्राथमिकियां, दस्तावेज, जब्त की गई सामग्री और सीसीटीवी फुटेज, अन्य चीजों के अलावा, तुरंत एन. आई. ए. को सौंप दी जानी चाहिए जो जांच शुरू करेगी और कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।पश्चिम बंगाल राज्य के पुलिस अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर सभी सामग्री एन. आई. ए. को सौंपने का निर्देश दिया गया था।4. सुनवाई के दौरान, हमने पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायण, एन. आई. ए. की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याची की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया और एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वकील सुश्री बांसुरी स्वराज को सुना है, जिन्होंने विचाराधीन घटनाओं से उत्पन्न शिकायत दर्ज कराई थी।

बी.

सी.

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन प्रमुख प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है, वे हैं:

डी.

(i) चार अलग-अलग तिथियों में छह अलग-अलग घटनाओं के संबंध में पुलिस द्वारा छह प्राथमिकियां दर्ज की गईं;

((ii) उच्च न्यायालय ने पिछले आदेशों पर काफी विस्तार से विचार किया है जो उसने एन. आई. ए. को जांच हस्तांतरित करने के लिए पारित किए थे।

ई.

((ग) उच्च न्यायालय ने दो आधारों पर विचार किया है: (क) 02 अप्रैल 2023 की एफ. आई. आर. 141 में बमों के कथित उपयोग के आरोप हैं; और

(ख) सभी चार जब्ती ज्ञापन एक ही लिखावट में प्रतीत होते हैं।

एफ.

(iv) उपरोक्त (क) के संबंध में, घायल शिकायतकर्ता को लगी चोटें केवल घर्षण का संकेत देती हैं जो ऐसी घटना से असंगत हैं। उपरोक्त (ख) के संबंध में, सात अलग-अलग पुलिस अधिकारियों ने अन्य बातों के साथ-साथ जब्ती ज्ञापन तैयार करने की जांच की थी।

जी.

(v) पश्चिम बंगाल राज्य में पुलिस अधिकारियों ने राज्य में राम नवमी समारोहों के दौरान हुई कथित घटनाओं के अनुसरण में विधिवत कार्रवाई की है; और

एच.

845

पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. v. एस. यू. वी. ए. एन. डी. आधिकाड़ी आ ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

(vi) एन. आई. ए. को जाँच के हस्तांतरण के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश आवश्यक नहीं है और कानून के अनुसार जाँच करने में पुलिस का मनोबल गिर जाएगा।

6. दूसरी ओर, एन. आई. ए. की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल और मूल याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश हुए वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। 7. एन. आई. ए. अधिनियम की धारा 6 (1) में किसी पुलिस स्टेशन

के प्रभारी अधिकारी से "किसी भी अनुसूचित अपराध से संबंधित" दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत सूचना की प्राप्ति और उसकी रिकॉर्डिंग पर तुरंत राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता होती है। "किसी भी अनुसूचित अपराध से संबंधित" अभिव्यक्ति एक व्यापक आयाम की अभिव्यक्ति है। धारा 6 की उप-धारा (2) में आदेश दिया गया है कि धारा 6 (1) के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार केंद्र सरकार को "जितनी जल्दी हो सके" रिपोर्ट भेजेगी। इसके बाद, उप-धारा (3) के संदर्भ में, केंद्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई या अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक निर्धारित अवधि के भीतर यह निर्धारित करना होगा कि क्या अपराध एक अनुसूचित अपराध है या नहीं और क्या अपराध की गंभीरता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह एजेंसी द्वारा जांच किया जाने वाला एक उपयुक्त मामला है। इस तरह की राय बनाने पर, केंद्र सरकार को उप-धारा (4) के तहत एन. आई. ए. को अपराध की जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है।

बी.

सी.

डी.

ई.

8. धारा 6 की उप-धारा (1) शुरू में किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर किसी भी अनुसूचित अपराध से संबंधित धारा 154 के तहत जानकारी प्राप्त होने पर राज्य सरकार को रिपोर्ट करने का सकारात्मक दायित्व डालती है। धारा 6 (2) राज्य सरकार पर यह कर्तव्य डालती है कि वह रिपोर्ट को केंद्र सरकार को शीघ्रता से भेजे। जहां तक केंद्र सरकार की भूमिका का संबंध है, उप-धारा (3) यह बहुत स्पष्ट करती है कि क्या अपराध एक अनुसूचित अपराध है और क्या अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एन. आई. ए. द्वारा जांच के लिए मामला एक उपयुक्त मामला है, इस पर राय का गठन न केवल उस जानकारी पर आधारित हो सकता है जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, बल्कि ऐसी जानकारी पर भी आधारित हो सकती है जो अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है। एन. आई. ए. को जाँच भेजने की केंद्र सरकार की शक्ति उस रिपोर्ट तक सीमित नहीं है जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है।

एफ.

जी.

एच.

846

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. केंद्र सरकार को, अपने अधिदेश के संदर्भ में, इस बात पर अपना ध्यान लगाना होगा कि पहला, अपराध एक अनुसूचित अपराध है या नहीं; और दूसरा, अपराध की गंभीरता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह एन. आई. ए. द्वारा जांच किए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

10. इन प्रावधानों से स्वतंत्र, धारा 6 की उप-धारा (5), जो एक अबाधित प्रावधान द्वारा प्रस्तुत की गई है, केंद्र सरकार को एन. आई. ए. को किसी अपराध की जांच करने का निर्देश देने के लिए स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देती है, जब वह यह राय बनाती है कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है जिसकी अधिनियम के तहत जांच की जानी आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा या तो उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने पर, राज्य सरकार और अपराध की जांच करने वाले राज्य सरकार के किसी भी पुलिस अधिकारी को जांच के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा और वे संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड को एन. आई. ए. को तुरंत हस्तांतरित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

बी.

सी.

11. विवादित आदेश में उच्च न्यायालय के निर्देश 27 अप्रैल 2023 को दिए गए थे। इसके बाद, 8 मई 2023 को केंद्र सरकार ने धारा 6 (5) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का संदर्भ देती है, लेकिन ऐसा करने के बाद, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि धारा 6 (5) के प्रावधानों के संदर्भ में भी शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था। इसके अनुसार, 10 मई 2023 को छह प्राथमिकियां दर्ज की गईं। विशेष न्यायालय द्वारा 11 मई 2023 को संज्ञान लिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया की प्रस्तुतियों में इंगित की गई घटनाओं का यह क्रम और जैसा कि सॉलिसिटर जनरल की प्रस्तुतियों में प्रमाणित किया गया है, विवाद में नहीं है। इसलिए, जैसा कि मामला है, एन. आई. ए. ने विशेष रूप से धारा 6 (5) के तहत अपनी शक्तियों के संदर्भ में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है।

डी.

ई.

एफ.

12. इस स्तर पर, न्यायालय को आरोपों की पर्याप्तता या उनकी सत्यता पर निर्णय लेने के लिए नहीं कहा जाता है। इस न्यायालय का अधिकार यह निर्धारित करने के लिए होगा कि क्या धारा

6 (5) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग धारा 6 (5) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के लिए बाहरी है ताकि इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

जी.

13. राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई छह प्राथमिकियां 30 मार्च 2023 और 3 अप्रैल 2023 के बीच थीं और चार पुलिस थानों में फैली हुई थीं। उनमें से दो प्राथमिकियां जो 31 मार्च 2023 को शिबपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई हैं, उन घटनाओं से संबंधित हैं जो ए एच.

847

पश्चिम बंगाल राज्य और ओ. आर. एस. v. एस. यू. वी. ए. एन. डी. आधिकाड़ी आ ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

यह 31 मार्च 2023 को हुआ था और समय के निकट है। इसी तरह, 2 अप्रैल 2023 और 3 अप्रैल 2023 को पुलिस स्टेशन सेरामपुर में दर्ज की गई प्राथमिकियों से भी यही स्थिति दिखाई देती है।

14. एन. आई. ए. द्वारा की जाने वाली जाँच की सटीक रूपरेखा का इस स्तर पर अनुमान या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। एन. आई. ए. न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है।

बी.

15. धारा 6 (5) के तहत जारी की गई अधिसूचना की वैधता को कोई चुनौती नहीं है।

16. इसलिए, हम विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, हालांकि उन कारणों के लिए जो ऊपर बताए गए हैं। 17. हम स्पष्ट करते हैं कि विवादित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां इस सवाल तक सीमित होंगी कि क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत एन. आई. ए. द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग वैध है। उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हैं।

सी.

डी.

18. विशेष अवकाश याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। 19. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

एस. एल. पी. का निपटान किया गया।

(सहायक: आरश चौधरी, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.